भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4188
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

बाल भिखारी

4188. श्री राजीव राय:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने बड़े शहरों और टियर-II शहरों में सड़क चौराहों और ट्रैफिक लाइटों पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;
- (ख) यदि हां, तो इन बच्चों की अनुमानित संख्या और औसत आयु वर्ग क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इन बच्चों के लिए कोई पुनर्वास योजना तैयार की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी दशा सुधारने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान कितना व्यय किया गया है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की योजना "स्माइल - आजीविका और उद्यम के लिए सीमांतवर्ती व्यक्तियों के लिए सहायता" कार्यान्वित करता है, जिसमें भीख मांगने वाले बच्चों सहित भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए उप-योजना शामिल है। इस उप-योजना के कार्यान्वयन के

पहले चरण में 31 चिन्हित शहरों/कस्बों में सर्वेक्षण/पहचान कार्य शामिल है। अब तक 6-14 वर्ष की औसत आयु वर्ग के 352 बच्चों की पहचान भीख मांगने वाले के रूप में की गई है। सभी 352 बच्चों का पुनर्वास किया जा चुका है (169 को उनके माता-पिता के पास भेज दिया गया, 79 को आंगनवाड़ी में भेज दिया गया, 33 को बाल कल्याण समिति में भेज दिया गया और 71 को स्कूलों में नामांकित कर दिया गया)। इस योजना के तहत भोजन, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधाएं, परामर्श, पुनर्वास, बुनियादी दस्तावेजीकरण, कौशल विकास, भीख मांगने वाले व्यक्तियों के बच्चों/बच्चों को शिक्षा सहित इकोनॉमिक लिंकेज जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) संचालित करता है, जो बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) की देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार और समाज में फिर से जोड़ कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके उनकी सुरक्षा का प्रावधान करता है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख एवं संरक्षण के मानकों को परिभाषित करता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (ii) में प्रावधान है कि कोई भी बच्चा जो तत्समय लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में कार्य करते हुए पाया जाता है या भीख मांगते हुए पाया जाता है या बेघर है, उसे 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' के रूप में शामिल किया गया है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 बाल कल्याण समितियों को बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी सीएनसीपी श्रेणी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की प्राथमिक जिम्मेदारी और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना में सीएनसीपी और सीसीएल श्रेणी के बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल हैं। इस योजना में बाल भिखारियों सहित बच्चों को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि तक पहुंच में सहायता करती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत सहायता देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात देखरेख के माध्यम से प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से 2023-24) के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत 4317.14 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अधिकृत किया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल भिक्षावृत्ति/बाल श्रम/बाल दुर्व्यवहार पर शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित जिलों में "सड़क पर रहने वाले बच्चों (सीआईएसएस) 2.0" पर मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार बच्चों की संख्या और आयु वर्ग का विवरण निम्नानुसार है:

आयु वर्ग (वर्ष में)	बच्चों की संख्या
0-6	1536
7-12	2537
13-18	1113